(ङ) और (च) आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। 1993–94 (जनवरी, 1994 तक) के दौरान आयात की मात्रा लगभग 4,98,618 मीटरी टन थी जब कि निर्यात कि मात्रा 33,087 मीटरी टन थी। वर्ष 1994–95 के लिए दालों के आयात और निर्यात का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है। आयात और निर्यात की मात्रा स्वदेशी उत्पादन, आंतरिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, आयात शुल्क और विदेशी बाजारों में उपलब्धता पर निर्भर करती है।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन दर/लागत

6044. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि क्षेत्र में उत्पादन लागत में कमी लाने और औसत उत्पादन दर में वृद्धि करने की अत्यंत आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कृषि क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान पर वहन किया जाने वाला व्यय कुल व्यय का मात्र 0.163 प्रतिशत के लगभग है ;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में कृषि का अपेक्षित विकास न हो पाने के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का अंश गत चार दशकों से निरंतर कम होता जा रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार कृषि क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान कार्य में गति लाने के लिए नए सिरे से विचार करके कोई कार्य योजना तैयार करेगी ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) उत्पादन लागत को घटाने तथा उत्पादन दर को बढ़ाने की गुंजाईश हमेशा रहती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाकर, फार्म प्रबंध विधियों आदि के माध्यम से उत्पादन लागत को घटाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है ;

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां। अधिक विकास संभावना वाले द्वितीय एवं तृतीयक क्षेत्रों के विकास से सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में कृषि का योगदान आमतौर पर घटता है।

(ङ) और (च) देश में अनुसंधान नेटवर्क 45 अनुसंधान संस्थानों, 40 राष्ट्रीय ब्यूरो, 30 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, 9 परियोजना निदेशालयों तथा 77 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से संचालित होता है। चूंकि फार्म अनुसंधान के लिए आबंटन पर्याप्त नहीं है, परिव्यय की अपर्याप्तता के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए अनुसंधान गतिविधियों का पुनर्गठन किया गया है।

देश में ऊसर भूमि

6045. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग 17.30 करोड़ हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय 14.20 करोड़ हैक्टेयर भूमि पर ही खेती की जा रही है, यदि नहीं तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने शेष कृषि योग्य भूमि को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शेष जुताऊ भूमि में से कितने प्रतिशत भूमि को कृषि हेतु उपयोग में लाया जाएगा ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1990–91 के भू-उपयोग के आंकड़ों (अध्यतन उपलब्ध) के अनुसार, देश में खेती योग्य कुल रकबा 184.35 मिलियन हैक्टेयर आंका गया था ।

(ख) भू-उपयोग के उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कृष्य रकबा (निवल बुआई क्षेत्र+चालू परती भूमि) 156.04 मिलियन हैक्टेयर आंका गया है ।

(ग) और (घ) सरकार अतिरिक्त क्षेत्र को खेती के रकबे में लाने के लिए भूमि सुधार तथा बंजर भूमि विकास संबंधी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्कीम नामतः क्षारीय मृदा सुधार के अंतर्गत 883 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 8.7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें केन्द्र सरकार का अंश 150 करोड़ रुपए है । इसके अलावा, बंजर भूमि विकास विभाग भी कुछ बंजर भूमि का उपचार कर रहा होगा ताकि उसे वायोमास उत्पादन, विशेषकर ईंधन, लकड़ी तथा चारा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सतत उपयोग में लाया जा सके, जिसके लिए अभी तक आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

स्माल फारमर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम

6046. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में छोटे किसानों के हितों के संरक्षण हेतु "स्माल फारमर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम" की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की गई थी ;

(ग) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शाखाएं भी स्थापित की गई हैं ताकि छोटे किसान इससे सहज रूप से लाभान्वित हो सकें ; और

(घ) यदि हां, तो किस-किस राज्य में कितनी-कितनी शाखाएं अब तक स्थापित की गई हैं और देश में कुल कितनी शाखाएं स्थापित करने का लक्ष्य है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) (क) जी, हां

(ख) दिनांक 18 जनवरी, 1994 को ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन द्वारा लाल मिर्च का निर्यात किया जाना

6047. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोओपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन पिछले कुछ वर्षों से लाल मिर्च का निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान किस-किस देश को कितनी-कितनी मात्रा में और कितने-कितने मूल्य की लाल मिर्च निर्यात की गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन वर्षों के दौरान घटिया किस्म की लाल मिर्च का भी निर्यात किया गया था जिसके कारण फैडरेशन को आर्थिक हानि हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो किस-किस देश को प्रत्येक वर्ष घटिया किस्म की लाल मिर्च का